SAFALTA CLASS™

An Initiative by अमर उजाला

INDIAN POLITY BY-

SUJEET BAJPAI SIR

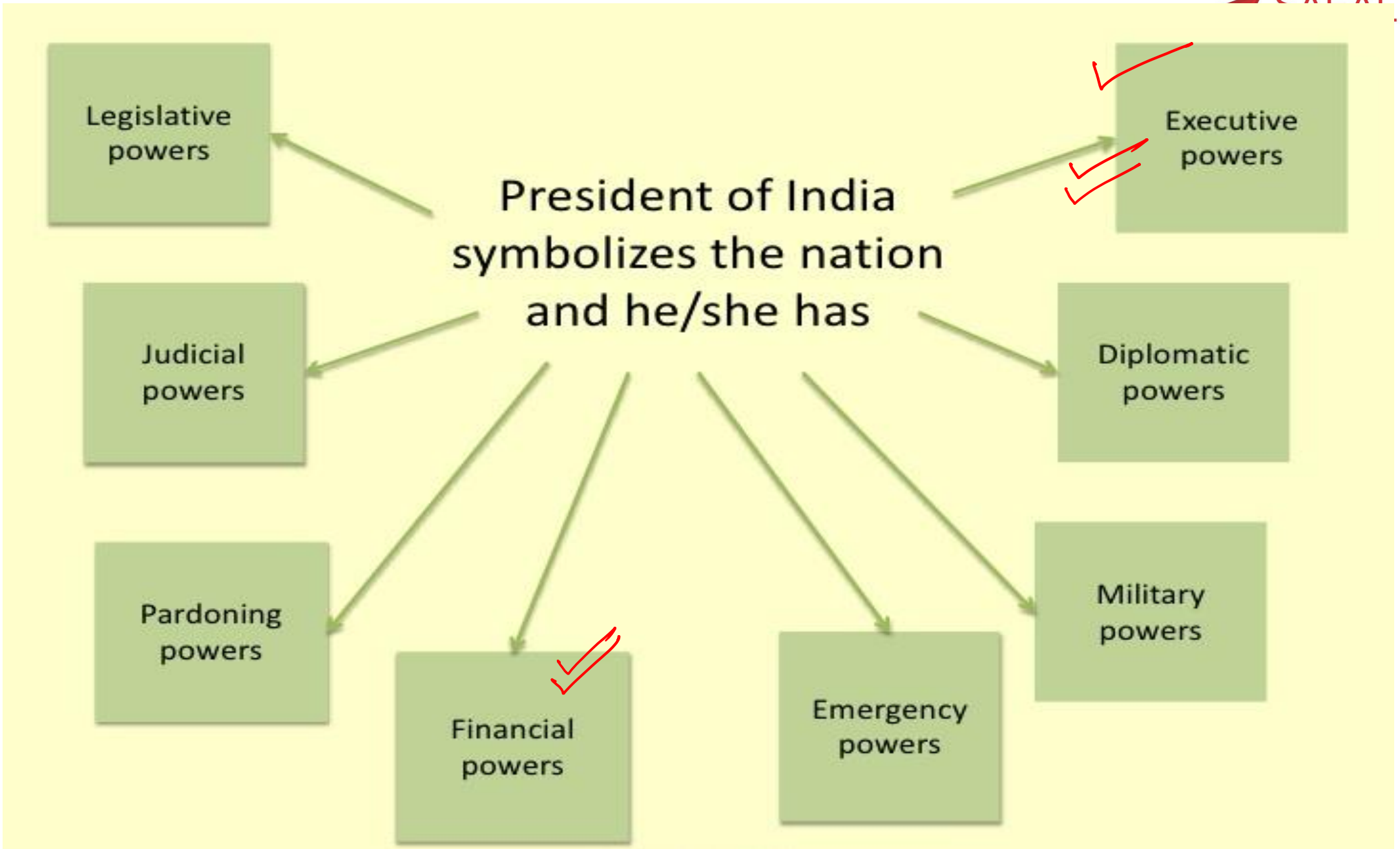
President of India symbolizes the nation and he/she has
Legislative powers
Executive powers
Judicial powers
Diplomatic powers
Pardoning powers
Financial powers
Emergency powers
Military powers

Judicial Powers

1.He appoints the Chief Justice and the judges of Supreme Court and high courts.

2. He can seek advice from the Supreme Court on any question of law or fact.

However, the advice tendered by the Supreme Court is not binding on the President.

न्यायिक शक्तियां

1. वह मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।
2. वह कानून या तथ्य के किसी भी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं।

हालांकि, उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है ।

3.He can grant pardon, reprieve, respite and remission of punishment, or suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence.

3. वह किसी भी अपराध के दोषी व्यक्ति की सजा को क्षमा, राहत, राहत और छूट, या निलंबित, परिहार या लघुकरण कर सकता है।

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

Diplomatic Powers

The international treaties and agreements are negotiated and concluded on behalf of the President.

राजनयिक शक्तियां राष्ट्रपति की ओर से अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौतों पर बातचीत और निष्कर्ष निकाला जाता है ।

Military Powers

He is the supreme commander of the defence forces of India.

In that capacity, he appoints the chiefs of the Army, the Navy and the Air Force. He can declare war or conclude peace, subject to the approval of the Parliament.

सैन्य शक्तियां वह भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं।

उस हैसियत से वह सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है।

वह युद्ध की घोषणा कर सकता है या संसद के अनुमोदन के अध लिए शांति समाप्त कर सकता है ।

National Emergency
in India

Emergency Powers

In addition to the normal powers mentioned above, the Constitution confers extraordinary powers on the President to deal with the following three types of emergencies:

(a)National Emergency (Article 352);

(b) President's Rule (Article 356 & 365); and

(c) Financial Emergency (Article 360)

1949-2020 | Never

आपातकालीन शक्तियां

उपर्युक्त सामान्य शक्तियों के अलावा, संविधान राष्ट्रपति को निम्नलिखित तीन प्रकार की आपात स्थितियों से निपटने के लिए असाधारण शक्तियां प्रदान करता है:

(क) राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352);

(ख) राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356 और 365); और

(ग) वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

The Emergency provisions are contained in Part XVIII of the Constitution, from Articles 352 to 360.

These provisions enable the Central government to meet any abnormal situation effectively.

आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग XVIII में अनुच्छेद ३५२ से ३६० तक निहित हैं ।

ये प्रावधान केंद्र सरकार को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाते हैं।

1.

An emergency due to war, external aggression or armed rebellion (Article 352).

This is popularly known as ‘National Emergency’.

However, the Constitution employs the expression ‘proclamation of emergency’ to denote an emergency of this type.

1. युद्ध, बाहरी आक्रामकता या सशस्त्र विद्रोह (अनुच्छेद 352) के कारण आपातकाल। इसे 'राष्ट्रीय आपातकाल' के नाम से जाना जाता है।

हालांकि, संविधान इस प्रकार की आपात स्थिति को निरूपित करने के लिए ' आपातकाल की उद्घोषणा ' की अभिव्यक्ति को नियोजित करता है ।

Originally, the Constitution mentioned ‘internal disturbance’ as the third ground for the proclamation of a National Emergency, but the expression was too vague and had a wider connotation.

Hence, the 44th Amendment Act of 1978 substituted the words ‘armed rebellion’ for ‘internal disturbance’.

मूल रूप से, संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के लिए तीसरे आधार के रूप में आंतरिक अशांति का उल्लेख किया गया था, लेकिन अभिव्यक्ति बहुत अस्पष्ट थी और इसका व्यापक अर्थ था ।

इसलिए, 1978 के 44 वें संशोधन अधिनियम ने आंतरिक अशांति के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्दों को प्रतिस्थापित किया।

Thus, it is no longer possible to declare a National Emergency on the ground of 'internal disturbance' as was done in 1975 by the Congress government headed by Indira Gandhi.

इस प्रकार, अब आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करना संभव नहीं है जैसा कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा १९७५ में किया गया था ।

Parliamentry Approval and Duration

The proclamation of Emergency must be approved by both the Houses of Parliament within one month from the date of its issue.

Originally, the period allowed for approval by the Parliament was two months, but was reduced by the 44th Amendment Act of 1978.

संसद अनुमोदन और अवधि आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने मुद्दे की तारीख से एक महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए ।

मूल रूप से, संसद द्वारा अनुमोदन के लिए अनुमति दी गई अवधि दो महीने की थी, लेकिन १९७८ के 44 वें संशोधन अधिनियम द्वारा कम कर दिया गया था ।

If approved by both the Houses of Parliament, the emergency continues for six months, and can be extended to an indefinite period with an approval of the Parliament for every six months.

यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो आपातकाल छह महीने तक जारी रहता है और इसे प्रत्येक छह महीने के लिए संसद की मंजूरी के साथ अनिश्चित अवधि तक बढ़ाया जा सकता है ।

Every resolution approving the proclamation of emergency or its continuance must be passed by either House of Parliament by a special majority, that is:

(a) a majority of the total membership of that house, and

(b) a majority of not less than two-thirds of the members of that house present and voting.

आपातकाल की उद्घोषणा या उसके जारी रहने को मंजूरी देने वाला प्रत्येक संकल्प संसद के किसी भी सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, अर्थात:

(क) उस सभा की कुल सदस्यता का बहुमत, और

(ख) उस सभा के दो-तिहाई से कम सदस्यों का बहुमत उपस्थित है और मतदान कर रहा है ।

Effect on the Fundamental Rights

Articles 358 and 359 describe the effect of a National Emergency on the Fundamental Rights.

Article 358 deals with the suspension of the Fundamental Rights guaranteed by Article 19, while Article 359 deals with the suspension of other Fundamental Rights (except those guaranteed by Articles 20 and 21).

A-352 comes in, A-19 goes out

मौलिक अधिकारों पर प्रभाव अनुच्छेद 358 और 359 मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करते हैं।

अनुच्छेद ३५८ अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीशुदा मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद ३५९ अन्य मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित है (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) ।

Declarations Made So Far This type of Emergency has been proclaimed three times so far—

1. 1962
2. 1971
3. 1975.

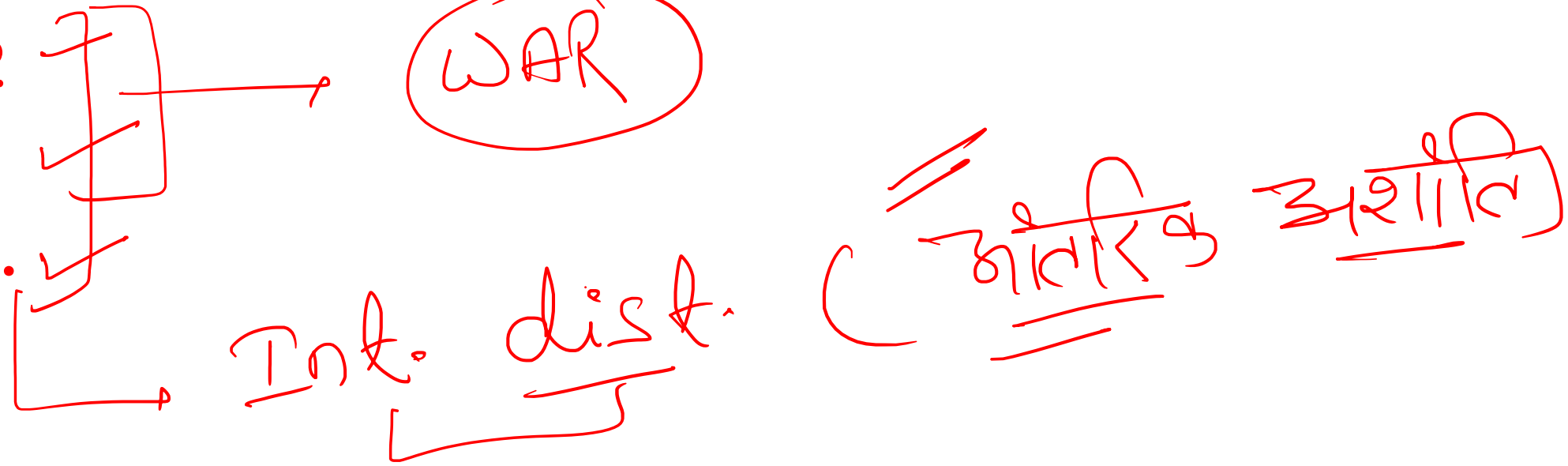

2.

An Emergency due to the failure of the constitutional machinery in the states (Article 356).

This is popularly known as ‘President’s Rule’.

It is also known by two other names—‘State Emergency’ or ‘constitutional Emergency’.

However, the Constitution does not use the word ‘emergency’ for this situation.

2. राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल (अनुच्छेद 356)।

इसे 'राष्ट्रपति शासन' के नाम से जाना जाता है। इसे दो अन्य नामों से भी जाना जाता है- 'राज्य आपातकाल' या 'संवैधानिक आपातकाल'।

हालांकि संविधान इस स्थिति के लिए आपातकाल शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है ।

3. Financial Emergency due to a threat to the financial stability or credit of India (Article 360).

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

Veto Power of the President

A bill passed by the Parliament can become an act only if it receives the assent of the President.

When such a bill is presented to the President for his assent, he has three alternatives (under Article 111 of the Constitution):

राष्ट्रपति की वीटो पावर संसद द्वारा पारित विधेयक तभी एक अधिनियम बन सकता है जब उसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाए। जब इस तरह के एक विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके पास तीन विकल्प (संविधान के अनुच्छेद १११ के तहत):

1. He may give his assent to the bill, or
2. He may withhold his assent to the bill, or
3. He may return the bill (if it is not a Money bill) for reconsideration of the Parliament.

However, if the bill is passed again by the Parliament with or without amendments and again presented to the President, the President must give his assent to the bill.

1. वह बिल के लिए अपनी सहमति दे सकता है, या
2. वह बिल के लिए अपनी सहमति रोक सकता है, या
3. वह संसद पर पुनर्विचार के लिए विधेयक (यदि यह धन विधेयक नहीं है) को वापस कर सकता है।

तथापि, यदि विधेयक संसद द्वारा संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के पुन पारित किया जाता है और फिर से राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी सहमति देनी चाहिए ।

The veto power enjoyed by the executive in modern states can be classified into the following four types:

1.

Absolute veto, that is, withholding of assent to the bill passed by the legislature.

2.

Qualified veto, which can be overridden by the legislature with a higher majority.

आधुनिक राज्यों में कार्यकारी द्वारा आनंद लिया वीटो शक्ति निम्नलिखित चार प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है:

1. पूर्ण वीटो, अर्थात विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर सहमति को रोक देना ।
2. योग्य वीटो, जो उच्च बहुमत के साथ विधायिका द्वारा अभिभूत किया जा सकता है ।

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

3. Suspensive veto, which can be over ridden by the legislature with an ordinary majority.

4. Pocket veto, that is, taking no action on the bill passed by the legislature.

Of the above four, the President of India is vested with three—absolute veto, suspensive veto and pocket veto.

3. सुस्पेंसिव वीटो, जो एक साधारण बहुमत के साथ विधायिका द्वारा ग्रस्त हो सकता है ।

4. पॉकेट वीटो, यानी विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है ।

उपरोक्त चार में से भारत के राष्ट्रपति के पास तीन-निरपेक्ष वीटो, निलंबन वीटो और पॉकेट वीटो निहित है ।

Ordinance-making Power of the President

Max → 6 m + 6 w

Art - 213

Article 123 of the Constitution empowers the President to promulgate ordinances during the recess of Parliament.

These ordinances have the same force and effect as an act of Parliament, but are in the nature of temporary laws.

अध्यादेश बनाने की शक्ति राष्ट्रपति संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है।

इन अध्यादेशों में संसद के एक अधिनियम के समान बल और प्रभाव होता है, लेकिन यह अस्थायी कानूनों की प्रकृति में होता है ।

In Cooper case, (1970), the Supreme Court held that the President's satisfaction can be questioned in a court on the ground of malafide.

कूपर मामले में, (१९७०) सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राष्ट्रपति की संतुष्टि के आधार पर एक अदालत में दुर्भावना के आधार पर पूछताछ की जा सकती है ।

D C Wadhwa case(1987)

Between 1967–1981 the Governor of Bihar promulgated 256 ordinances and all these were kept in force for periods ranging from one to fourteen years by repromulgation from time to time.

डी सी वाधवा मामला (1987) 1967-1981 के बीच बिहार के राज्यपाल ने 256 अध्यादेश आयोजित किए और इन सभी को समय-समय पर पुनर्प्रोजय करके एक से चौदह वर्ष तक की अवधि के लिए लागू रखा गया।

The court ruled that successive repromulgation of ordinances with the same text without any attempt to get the bills passed by the assembly would amount to violation of the Constitution and the ordinance so repromulgated is liable to be struck down.

अदालत ने फैसला सुनाया कि विधानसभा द्वारा विधेयकों को पारित कराने के किसी भी प्रयास के बिना एक ही पाठ के साथ अध्यादेशों का लगातार पुनर्मूल्यांकन संविधान के उल्लंघन के लिए राशि होगी और इस प्रकार पुनर्मूल्यांकन किए गए अध्यादेश को निरस्त किया जाना उत्तरदायी है ।

POWER OF PARDON
Diff/B Pardoning power of President and Governor

Pardoning Power of the President(Article-72)

1.Pardon It removes both the sentence and the conviction and completely absolves the convict from all sentences, punishments and disqualifications.

2.Commutation It denotes the substitution of one form of punishment for a lighter form.

For example, a death sentence may be commuted to rigorous imprisonment, which in turn may be commuted to a simple imprisonment.

राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति (अनुच्छेद-72)

1. क्षमा यह सजा और सजा दोनों को हटा देता है और दोषी को सभी वाक्यों, दंड और अयोग्यता से पूरी तरह से मुक्त करता है।

2. कम्यूटेशन यह एक हल्के रूप के लिए सजा के एक रूप के प्रतिस्थापन को दर्शाता है।

उदाहरण के लिए, मौत की सजा को कठोर कारावास में बदल दिया जा सकता है, जिसे बदले में साधारण कारावास में बदल दिया जा सकता है ।

Time-2

3.Remission It implies reducing the period of sentence without changing its character.

For example, a sentence of rigorous imprisonment for two years may be remitted to rigorous imprisonment for one year.

3. छूट यह अपने चरित्र को बदलने के बिना वाक्य की अवधि को कम करने का तात्पर्य है।

उदाहरण के लिए, दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा को एक वर्ष के लिए कठोर कारावास तक भेजा जा सकता है।

A Type of Remission

4.

Respite It denotes awarding a lesser sentence in place of one originally awarded due to some special fact, such as the physical disability of a convict or the pregnancy of a woman offender.

4. राहत यह मूल रूप से कुछ विशेष तथ्य के कारण दिए गए एक के स्थान पर कम सजा देने को दर्शाता है, जैसे किसी दोषी की शारीरिक अक्षमता या महिला अपराधी की गर्भावस्था ।

5. Reprieve It implies a stay of the execution of a sentence (especially that of death) for a temporary period.

Its purpose is to enable the convict to have time to seek pardon or commutation from the President.

5. राहत यह एक अस्थाई अवधि के लिए एक वाक्य (विशेष रूप से मौत की है कि) के निष्पादन के रहने का तात्पर्य है ।

इसका उद्देश्य दोषी को राष्ट्रपति से क्षमा या परिवर्तन प्राप्त करने के लिए समय देना है ।

Under Article 161 of the Constitution, the governor of a state also possesses the pardoning power.

Hence, the governor can also grant pardons, reprieves, respites and remissions of punishment or suspend, remit and commute the sentence of any person convicted of any offence against a state law.

संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत किसी राज्य के राज्यपाल के पास क्षमा शक्ति भी है।

इसलिए, राज्यपाल राज्य के कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के दोषी किसी भी व्यक्ति की सजा को क्षमा, राहत, राहत और छूट या निलंबित, परिहार और लघुकरण भी प्रदान कर सकते हैं ।

But, the pardoning power of the governor differs from that of the President in following two respects:

1. The President can pardon sentences inflicted by court martial (military courts) while the governor cannot.

लेकिन, राज्यपाल की क्षमा शक्ति दो मामलों का पालन करने में राष्ट्रपति से अलग है:

1. राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल (सैन्य अदालतों) द्वारा दिए गए वाक्यों को क्षमा कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल नहीं कर सकते ।

2. The President can pardon death sentence while governor cannot.

Even if a state law prescribes death sentence, the power to grant pardon lies with the President and not the governor.

2. राष्ट्रपति मौत की सजा क्षमा कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल नहीं कर सकते ।

यहां तक कि अगर एक राज्य के कानून मौत की सजा निर्धारित करता है, क्षमा देने की शक्ति राष्ट्रपति और नहीं राज्यपाल के पास है ।

⇒ Prime min =

In the scheme of parliamentary system of government provided by the constitution, the President is the nominal executive authority (de jure executive) and Prime Minister is the real executive authority (de facto executive).

संविधान द्वारा प्रदान की गई सरकार की संसदीय प्रणाली की योजना में, राष्ट्रपति नाममात्र का कार्यकारी प्राधिकरण (डी ज्यूर कार्यकारी) है और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण (वास्तविक कार्यकारी) है ।

Appointment of the Prime Minister

The Constitution does not contain any specific procedure for the selection and appointment of the Prime Minister. Article 75 says only that the Prime Minister shall be appointed by the president.

प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान में प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया शामिल नहीं है।

अनुच्छेद 75 में केवल इतना कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।

In accordance with the conventions of the parliamentary system of government, the President has to appoint the leader of the majority party in the Lok Sabha as the Prime Minister.

सरकार की संसदीय प्रणाली के अधिवेशनों के अनुसार राष्ट्रपति को लोकसभा में बहुमत वाले दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करना होता है।

But, when no party has a clear majority in the Lok Sabha, then the President may exercise his personal discretion in the selection and appointment of the Prime Minister.

लेकिन, जब लोकसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति में अपने व्यक्तिगत विवेक का प्रयोग कर सकता है।

In such a situation, the President usually appoints the leader of the largest party or coalition in the Lok Sabha as the Prime Minister and asks him to seek a vote of confidence in the House within a month.

ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आमतौर पर लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं और उन्हें एक महीने के भीतर सदन में विश्वास मत मांगने को कहते हैं।

This discretion was exercised by the President, for the first time in 1979, when Neelam Sanjiva Reddy (the then President) appointed Charan Singh (the coalition leader) as the Prime Minister after the fall of the Janata Party government headed by Morarji Desai.

राष्ट्रपति ने इस विवेक का प्रयोग पहली बार 1979 में किया था, जब नीलम संजीव रेड्डी (तत्कालीन राष्ट्रपति) ने मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार के पतन के बाद चरण सिंह (गठबंधन के नेता) को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था ।

However, if, on the death of an incumbent Prime Minister, the ruling party elects a new leader, the President has no choice but to appoint him as Prime Minister.

हालांकि, अगर किसी मौजूदा प्रधानमंत्री की मौत पर सत्तारूढ़ दल नए नेता का चुनाव करता है तो राष्ट्रपति के पास उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करने के अलावा कोई चारा नहीं है।

In 1997, the Supreme Court held that a person who is not a member of either House of Parliament can be appointed as Prime Minister for six months, within which, he should become a member of either House of Parliament; otherwise, he ceases to be the Prime Minister.

१९९७ में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि जो व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे छह महीने के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, जिसके भीतर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना चाहिए; अन्यथा, वह प्रधानमंत्री बने रहते हैं ।

Constitutionally, the Prime Minister may be a member of any of the two Houses of parliament.

For example, three Prime Ministers, Indira Gandhi (1966), Deve Gowda (1996) and Manmohan Singh (2004), were members of the Rajya Sabha.

In Britain, on the other hand, the Prime Minister should definitely be a member of the Lower House (House of Commons).

संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं।

उदाहरण के लिए तीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी (1966), देवगौड़ा (1996) और मनमोहन सिंह (2004) राज्यसभा के सदस्य थे।

दूसरी ओर ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को निश्चित रूप से निचले सदन (हाउस ऑफ कॉमन्स) का सदस्य होना चाहिए ।

The term of the Prime Minister is not fixed and he holds office during the pleasure of the president.

However, this does not mean that the president can dismiss the Prime Minister at any time.

So long as the Prime Minister enjoys the majority support in the Lok Sabha, he cannot be dismissed by the President.

However, if he loses the confidence of the Lok Sabha, he must resign or the President can dismiss him.

प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं है और वह राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं ।

हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति 2014 में प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं।

जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है, तब तक उन्हें राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त नहीं किया जा सकता ।

हालांकि अगर वह लोकसभा का विश्वास खो देते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या राष्ट्रपति उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं।

Lord Morely He described Prime Minister as ‘primus inter pares’ (first among equals) and ‘key stone of the cabinet arch’.

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

ARTICLE	PROVISIONS
Art. 74	Council of Ministers to aid and advise the President
Art. 75	Other provisions as to ministers
Art. 77	Conduct of business of the Government of India
Art. 78	Duties of PM as respects the furnishing of information to the President etc.

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

Analyze the Difference Between the Cabinet and Council of Ministers

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

Collective Responsibility

The fundamental principle underlying the working of parliamentary system of government is the principle of collective responsibility.

Article 75 clearly states that the council of ministers is collectively responsible to the Lok Sabha.

सामूहिक जिम्मेदारी

सरकार की संसदीय प्रणाली के कार्यशील मौलिक सिद्धांत सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है ।

अनुच्छेद 75 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।

This means that all the ministers own joint responsibility to the Lok Sabha for all their acts of ommission and commission.

They work as a team and swim or sink together.

इसका मतलब यह है कि सभी मंत्रियों के पास अपने सभी कार्यों के लिए लोकसभा की संयुक्त जिम्मेदारी है ।

वे एक टीम के रूप में काम करते हैं और तैरते हैं या एक साथ डूबते हैं।

The Governor

Appointment, Functions and Powers

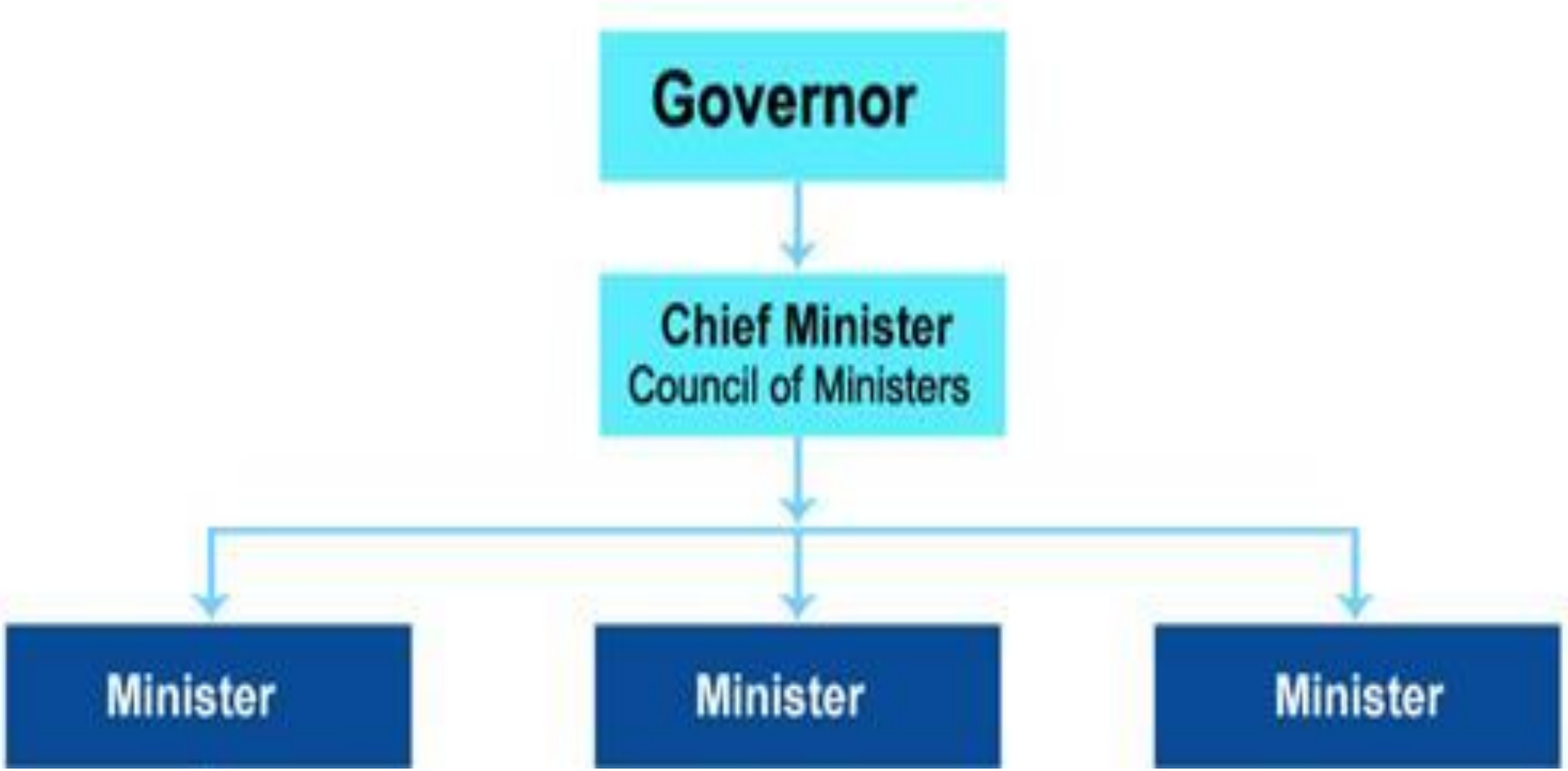
Governor
Chief Minister
Council of Ministers
Minister
Minister
Minister

Articles 153 to 167 in Part VI of the Constitution deal with the state executive.

Appointment of Governor

Term X

The governor is neither directly elected by the people nor indirectly elected by a specially constituted electoral college as is the case with the president.

He is appointed by the president by warrant under his hand and seal. In a way, he is a nominee of the Central government.

राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल न तो सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और न ही अप्रत्यक्ष रूप से विशेष रूप से गठित निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं जैसा कि राष्ट्रपति के मामले में है ।

उसके हाथ और मुहर के नीचे वारंट द्वारा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है ।

एक तरह से वह केंद्र सरकार के उम्मीदवार हैं।

But, as held by the Supreme Court in 1979, the office of governor of a state is not an employment under the Central government.

It is an independent constitutional office and is not under the control of or subordinate to the Central government.

लेकिन, जैसा कि 1979 में उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था, किसी राज्य के राज्यपाल का पद केन्द्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है।

यह एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है और यह केन्द्र सरकार के नियंत्रण में या अधीनस्थ नहीं है।

Term of Governor's Office

A governor holds office for a term of five years from the date on which he enters upon his office.

However, this term of five years is subject to the pleasure of the President.

Further, he can resign at any time by addressing a resignation letter to the President.

राज्यपाल कार्यालय का कार्यकाल एक राज्यपाल उस तारीख से पांच साल की अवधि के लिए कार्यालय रखता है जिस पर वह अपने कार्यालय में प्रवेश करता है ।

हालांकि, पांच साल का यह कार्यकाल राष्ट्रपति की खुशी के अधीन है ।

अलावा राष्ट्रपति को इस्तीफा पत्र देकर वह ारा कतई भी इस्तीफा दे सकते हैं।

The powers and functions of the governor can be studied under the following heads:

1. **Executive powers.**
2. **Legislative powers.**
3. **Financial powers.**
4. **Judicial powers.**

1. Executive powers.

1.

He appoints the chief minister and other ministers. They also hold office during his pleasure.

There should be a Tribal Welfare minister in the states of Chattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh and Odisha appointed by him.

1. वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं।

वे अपनी प्रसाद पर्यंत पद भी धारण करते हैं ।

उनके द्वारा नियुक्त छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्यों में आदिवासी कल्याण मंत्री होना चाहिए।

2.

He appoints the advocate general of a state and determines his remuneration. The advocate general holds office during the pleasure of the governor.

2. वह किसी राज्य के एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है और उसका पारिश्रमिक तय करता है।

एडवोकेट जनरल राज्यपाल की प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं ।

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

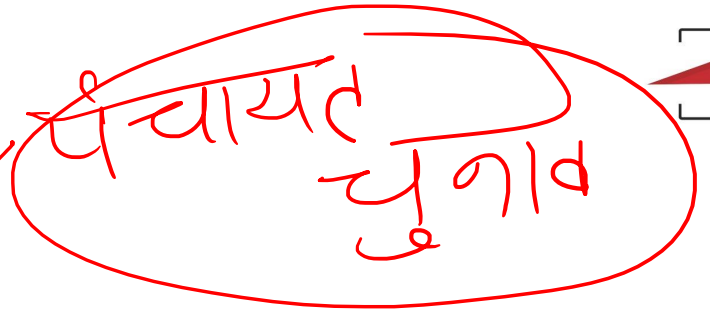

3.

He appoints the state election commissioner and determines his conditions of service and tenure of office. However, the state election commissioner can be removed only in like manner and on the like grounds as a judge of a high court.

3. वह राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं और उनकी सेवा शर्तों और पद के कार्यकाल का निर्धारण करते हैं ।

हालांकि, राज्य चुनाव आयुक्त को केवल समान तरीके से और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में समान आधार पर हटाया जा सकता है ।

4.

He appoints the chairman and members of the state public service commission.

However, they can be removed only by the president and not by a governor.

4. वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। हालांकि, उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है न कि किसी राज्यपाल द्वारा ।

2. Legislative powers.

A governor is an integral part of the state legislature. In that capacity, he has the following legislative powers and functions:

1. **He can summon or prorogue the state legislature and dissolve the state legislative assembly.**

एक राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है। उस क्षमता में, उसके पास निम्नलिखित विधायी शक्तियां और कार्य हैं:

1. वह राज्य विधानमंडल को बुला सकता है या उसका प्रस्ताव कर सकता है और राज्य विधान सभा को भंग कर सकता है ।

2. He can address the state legislature at the commencement of the first session after each general election and the first session of each year.

2. वह प्रत्येक आम चुनाव और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में राज्य विधानमंडल को संबोधित कर सकते हैं ।

3. He nominates one-sixth of the members of the state legislative council from amongst persons having special knowledge or practical experience in literature, science, art, cooperative movement and social service.

3. वह साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों के बीच से राज्य विधान परिषद के सदस्यों में से 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है ।

4. He can nominate one member to the state legislature assembly from the Anglo-Indian Community.

5.He can promulgate ordinances when the state legislature is not in session.

These ordinances must be approved by the state legislature legislature within six weeks from its reassembly.

5. जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं होता है तो वह अध्यादेश ोंः को प्रख्यापित कर सकता है ।

इन अध्यादेशों को राज्य विधानमंडल द्वारा अपनी पुनर्विधानसभा से छह सप्ताह के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए ।

Financial Powers

The financial powers and functions of the governor are:

1. **He sees that the Annual Financial Statement (state budget) is laid before the state legislature.**

वित्तीय शक्तियां राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां और कार्य हैं:

1. वह देखता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण (राज्य बजट) राज्य विधानमंडल के सामने रखा गया है ।

2. Money bills can be introduced in the state legislature only with his prior recommendation.

3. No demand for a grant can be made except on his recommendation.

2. राज्य विधानमंडल में केवल उनकी पूर्व सिफारिश के साथ ही धन विधेयक पेश किए जा सकते हैं।

3. उनकी सिफारिश को छोड़कर अनुदान की कोई मांग नहीं की जा सकती है।

4. He can make advances out of the Contingency Fund of the state to meet any unforeseen expenditure.

5. He constitutes a finance commission after every five years to review the financial position of the panchayats and the municipalities

4. वह किसी भी अप्रत्याशित खर्च को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम कर सकता है।

5. वह पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर पांच साल के बाद एक वित्त आयोग का गठन करता है।

Judicial Powers

The judicial powers and functions of the governor are:

1.

He can grant pardons, reprives, respites and remissions of punishment or suspend, remit and commute the sentence of any person convicted of any offence against any law relating to a matter to which the executive power of the state extends.

न्यायिक शक्तियां राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां और कार्य हैं:

1.

वह किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के दोषी किसी भी व्यक्ति की सजा को क्षमा, फटकार, राहत, राहत, राहत और छूट या निलंबित, परिहार और लघुकरण कर सकता है, जिसके लिए राज्य की कार्यकारी शक्ति फैली हुई है ।

2.

He is consulted by the president while appointing the judges of the concerned state high court.

153.	Governors of states
154.	Executive power of state
155.	Appointment of Governor
156.	Term of office of Governor
157.	Qualifications for appointment as Governor
158.	Conditions of Governor's office
159.	Oath or affirmation by the Governor
160.	Discharge of the functions of the Governor in certain contingencies

161.	Power of the Governor to grant pardons and others
162.	Extent of executive power of state
163.	Council of ministers to aid and advise the Governor
164.	Other provisions as to ministers like appointments, term, salaries, and others
165.	Advocate-General for the state
166.	Conduct of business of the government of a state
167.	Duties of the Chief Minister regarding furnishing of information to the Governor, and so on

174.	Sessions of the state legislature, prorogation and dissolution
175.	Right of the Governor to address and send messages to the house or houses of state legislature
176.	Special address by the Governor
200.	Assent to bills (i.e. assent of the Governor to the bills passed by the state legislature)
201.	Bills reserved by the Governor for consideration of the President
213.	Power of Governor to promulgate ordinances

217.	Governor being consulted by the President in the matter of the appointments of the judges of the High Courts
233.	Appointment of district judges by the Governor
234.	Appointments of persons (other than district judges) to the judicial service of the state by the Governor.

Don’t Forget to Like / Comment & Share this video

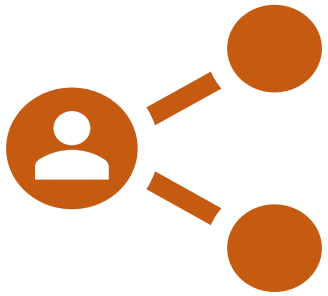

www.Youtube.com/safaltaclass

www.Facebook.com/safaltaclass

www.Instagram.com/safaltaclass

Google Play Store

SAFALTACLASS